(b) to (d) It is not in public interest to divulge the details of the report or the action proposed to be taken thereon, at this stage.

Minister's Visit to Switzerland

2047. SHRI GURUDAS DAS GUPTA:
SHRI N. E. BALARAM:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that he attended a meeting or a seminar at Switzerland in February, 1986;

(b) if so, did he refer to a study of eleven top American Companies' dividend repatriation;

(c) who conducted the study;

(d) which American companies were studied;

(e) what are the total investments of these companies and how much has been repatriated as profits over the year;

(f) whether this rate of dividend out-flow is a part of Government for attracting foreign investment; and

(g) whether such a policy be beneficial for the Indian economy?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) and (b) Yes, Sir.

(c) to (g) The study has been conducted by the Indo-American Chamber of Commerce. The Chamber has not given the list of these 11 companies. As per the report of the Chamber, 11 U.S. companies had contributed a total capital of $4.84 million on which they earned divident of $11.6 million during a period of five years from 1975 to 1980 (or in some cases from 1976 to 1981).

The rate of dividend is not governed by Government but is determined by the companies on the basis of their profitability.

Jobs for Retired Chief Election Commissioner

2048. SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state:

(a) what is the number and names of the retired Chief Election Commissioners of India who were appointed to other jobs after the expiry of term of their office in the past; and

(b) whether there is any proposal not to engage retired Chief Election Commissioners in any task after the expiry of their terms?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI H. R. BHARDWAJ): (a) Of the seven Chief Election Commissioners who have held office since 1950 to 1985, four were appointed to other jobs after the expiry of their term. They are as under:—

1. Shri Sukumar Sen
2. Shri K. V. K. Sundaram
3. Shri S. P. Sen Verma
4. Shri R. K. Trivedi.

(b) No, Sir.

Reduction of stamp duty on DDA flats

2049. DR. GOVIND DAS RICHHARIA: Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state:

(a) whether any requests have been received by Government to reduce stamp duty charged at the time of registration of flats of the Middle Income Group constructed and allotted by the Delhi Development Authority in the Union Territory of Delhi and to recover it on the basis of prices fixed for land;

(b) if so, what are the details thereof and what decision has been taken by Government thereon; and

(c) whether Government propose to give any relief to these people also as was given to the allottees of flats under the Low Income Group; if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI H. R. BHARDWAJ): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

न्यायालयों के निर्णयों का हिंदी में दिया जाना

2050. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के किन-किन राज्यों में कानूनी शिक्षा राजभाषा हिन्दी के माध्यम से दी जाती है तथा न्यायाधीश भी अपने निर्णय इसी भाषा में सुनाते हैं;

(ख) उनके मंत्रालय द्वारा और अधिक न्यायालयों मे राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा तथा उसके प्रचार को सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ग) पिछले 22 वर्षों से राजभाषा अधिनियम को तथा पिछले 17 वर्षों से हिन्दी के वार्षिक प्रगामी कार्यक्रम को लागू न किए जाने के क्या कारण हैं।

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) और (ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात राज्य में निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में, प्रथम उपाधि स्तर पर विधि पाठ्यक्रमों के लिए अंग्रेजी के अतिरिक्त, हिन्दी माध्यम भी उपलब्ध है।

बिहार :

(1) मगध (2) एल० एन० मिथिला (3) पटना

मध्य प्रदेश :

(1) ए० पी० सिंह (2) जबलपुर (3) जीवाजी (4) रवि शंकर (5) विक्रम (6) इन्दौर

राजस्थान :

(1) राजस्थान (3) उदय पुर

उत्तर प्रदेश :

(1) आगरा (2) इलाहाबाद (3) अवध (4) काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (5) बुंदेलखंड (6) गढ़वाल (7) गोरखपुर (9) कुमायूं (10) लखनऊ (11) मेरठ (12) रुहेलखंड

गुजरात

(1) गुजरात (2) सरदार पटेल (3) सौराष्ट्र, और (4) दक्षिणी गुजरात।

संविधान के अनुच्छेद 348 (2) और राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 7 के अधीन, किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से, अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी या उस राज्य की राजभाषा का प्रयोग, उस राज्य के उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में और उसके द्वारा पारित या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेशों के प्रयोजनो के लिए प्राधिकृत कर सकेगा। इस प्रकार किसी राज्य के उच्च न्यायालय में हिन्दी या उस राज्य की राजभाषा के प्रयोग के बारे में पहल करना राज्य सरकार का ही कार्य है। केन्द्रीय सरकार की भूमिका तभी प्रारंभ होती है जब उक्त संवैधानिक और विधिक उपबंधों के अधीन राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति अभिप्राप्त करने का प्रश्न उठता है। अभी तक, चार उच्च न्यायालयों को, अर्थात् इलाहाबाद, पटना, राजस्थान और मध्य प्रदेश उच्चन्यायालय को, अपनी - कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी में करने और निर्णय, आदि देने के लिए प्राधिकृत किया गया है।